भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3507

10 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

शहरी रोजगार गारंटी योजना

3507. श्री नलीन कुमार कटील:

श्री डी. के. सुरेशः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शहरी रोजगार गारंटी योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्यों ने शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कोई सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): शहरी गरीबी उन्मूलन सहित शहरी विकास राज्य का विषय है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के उद्देश्य से देश भर के सभी वैधानिक शहरों में प्रभावी ढंग से "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके माध्यम से वे लाभकारी स्व-रोजगार और कार्य कुशल मजदूरी रोजगार सक्षम बनें और परिणामस्वरूप इसके विभिन्न घटकों जैसे कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट (ईएसटीपी), स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार हो। इसके अलावा, शहरी गरीबों को रोजगार के अवसर, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अन्य मंत्रालयों द्वारा भी इसी तरह की अन्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में, सरकार का शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ): राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहरी रोजगार गारंटी योजना त्रिपुरा (त्रिपुरा शहरी रोजगार कार्यक्रम, 2009 से), केरल (अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना, 2010 से), पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना, 2010 से), ओडिशा (मुख्यमंत्री कर्मतत्परा अभियान, अप्रैल, 2020 से), हिमाचल प्रदेश (मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, मई, 2020 से) और झारखंड (मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, अगस्त 2020 से) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राजस्थान राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी बजट घोषणा में शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की थी। भारत सरकार इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को कोई सहायता प्रदान नहीं कर रही है।

*****